U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C

ना पहाड़ों से डरते, ना तूफानों से डगमगाते हैं, जो तूफानों से टकराते हैं
और डाक कर्मचारियों के दु:खों को दूर करने के लिए लड़ते हैं उसे
FNPO-NUPE Postmen & Group-D/MTS Union कहते हैं।।

POSTAL PRAKASH

सी.एच.क्यू., दलवी सदन, खुर्शीद स्क्वायर, सिविल लाईंस, दिल्ली-110054

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs. 50/- Single Copy Rs. 5/-

Editor : T.N. RAHATE Vol. No. XXX - No. 10 OCTOBER, 2014

HINDI ISSUE

Contents

Page 1
जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट

Page 2
Secretary (Posts) appealed to donate one day's salary to Prime Minister's National Relief Fund

Page 3
Postal JCA decides to intensify the struggle

Page 7
General Secretary Letter Addressed to Secretary (P) regarding grant of MACP by ignoring TBOP/BCR

Page 8
Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988

Page 9
Memorandum submitted to 7th CPC has been acknowledged by the Commission

Page 10
Agenda Items for Periodical Meeting

Page 16
No Trade Union Facilities Given to Bharatiya Postal Employees Federation and its affiliated Unions

जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट

1से 21-09-14 तक मुंबई (महाराष्ट्र) में ही रहा।

22-09-14 से गुजरात सर्कल में रहा। CPMG के साथ मीटिंग लेकर गुजरात की समस्या और खेड़ा डिवीजन की समस्या के बारे में चर्चा की। CPMG ने खेड़ा डिवीजन की समस्या PMG वडोदरा से भी चर्चा करने के लिए कहा एवं उन्हें फोन पर समस्या हल करने के लिए कहा। हमारे सभी P-IV, P-III के सर्कल सचिव साथ रहे। तुरंत बड़ौदा गये और PMG से खेड़ा डिवीजन की समस्या के बारे में चर्चा की, DPS से सारी डिटेल चौकशी करके समाधानकारक हल निकालेंगे और SP पर भी कार्यवाही की जायेगी।

23-9-14, मथुरा (यू.पी सर्कल) में रहा। SSPO मथुरा से मिलकर श्री कैलासचंद शर्माजी की ग्रेज्यूटी में से **1,90,325 रुपये** रिकवर करके UCR में जमा किये, उनको कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी थी। इस बारे में चर्चा की उन्हें मथुरा HO और DAP लखनऊ से बातचीत करके जल्दी हल निकालेंगे और DG के साथ चर्चा करने के लिए रिकवरी की, इस बारे में मथुरा HO DO और DAP लखनऊ ने किये पत्र व्यवहार और लिखकर प्रति यूनियन को देंगे। आप DG के साथ चर्चा करके क्लेरीफिकेशन देने की विनती की। (मथुरा डिवीजन सचिव-प्रेसीडेंट और कायकर्ता साथ थे। तुरंत भरतपुर (राजस्थान सर्कल) में गये। भरतपुर डिवीजन की समस्या P-IV और P-III डिवीजन सेक्रेटरी से सुनी और CPMG के पास चर्चा करने के लिए जयपुर गये।

शेष पृष्ठ 15 पर...

Journal of The National Union of Postal Employees, Postmen and Group 'D'/MTS
P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054. **Tel.:** 23818330 • **Email :** tnrahate@yahoo.com
Shri T.N. Rahate (General Secretary) **M.:** 08080070500, 09869121277
Web : www.nupepostmen.org • www.nupepostmenp4.blogspot.com

Secretary (Posts) appealed to donate one day's salary to Prime Minister's National Relief Fund

कावेरी बनर्जी
सचिव
Kavery Banerjee
Secretary
फोन/Tel.: (+91-11) 2309 6060
फैक्स/Fax : (+91-11) 2309 6077
ई-मेल/E-mail : secretary-posts@indiapost.gov.in

RIGHT TO INFORMATION

सत्यमेव जयते

डाक विभाग
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार
डाक भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001
Department of Posts
Ministry of Communications & IT
Government of India
Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110001

No. 92-52-2014-Coord./O&M 24th September, 2014

APPEAL

We are all aware of the devastating floods that have hit Jammu & Kashmir in September, 2014 and have caused immense damage to life and property.

2. You would agree that we need to stand by our affected brothers and sisters in their hour of need and try to alleviate their distress and misery.

3. I would, therefore, urge each one of you to consider donating one day's salary to aid victims of such natural disaster.

4. This would be a voluntary exercise. In case, you wish to contribute towards the relief efforts, you may communicate your willingness in writing to the Head of the Department / Drawing & Disbursing Officer, for effecting deduction from your salary which would be donated to the Prime Minister's Relief Fund. I may mention that all donations towards this Fund are liable for 100% deduction from taxable income under Section 80G of the Income Tax Act, 1961.

5. I am sure you would share in the concerns for the flood affected people of Jammu & Kashmir, and would not hesitate to do your bit towards supporting the relief measures. I look forward to your wholehearted cooperation in this venture.

(Kavery Banerjee)

POSTAL JCA DECIDES TO INTENSIFY THE STRUGGLE

POSTAL JOINT COUNCIL OF ACTION
NATIONAL FEDERATION OF POSTAL EMPLOYEES
1st Floor, North Avenue Post office Building, New Delhi – 110001
FEDERATION OF NATIONAL POSTAL ORGANISATIONS
T-24, Atul Grove Road, New Delhi – 110001

No. JCA/AGTN/2014 Dated - 26.09.2014

POSTAL JCA DECIDES TO INTENSIFY THE STRUGGLE FURTHER
20,000 Postal & RMS Employees Including Gramin Dak Sevaks will march towards Parliament on 04.12.2014

A meeting of the Postal Joint Council of Action (PJCA) was held at New Delhi on 25.09.2014 under the Presidentship of Shri D.Theagarajan, Secretary General, FNPO General Secretaries and other leaders of all affiliated Unions of NFPE & FNPO attended the meeting. Com. M.Krishnan, Ex-Secretary General, NFPE was also present. Com. R.N. Parashar, Secretary General, NFPE placed the review report regarding the implementation of the phased programmes of action of JCA conducted so far. After detailed deliberations the following decisions are taken.

Secretary, Department of Posts, has informed that it will furnish the item-wise reply to the demands raised in the charter of demands to the PJCA shortly. After receipt of reply from the Department, the JCA will meet again and future course of action will be decided.

2. It was decided to organize as massive Parliament march on 4th December 2014 (04.02.2014 Thursday) demanding immediate settlement of Charter of demands. More than 20000 Postal & RMS employees including Gramin Dak Sevaks will be mobilized in the March to Parliament (Date changed from 10.12.2014 to 04.12.2014 as the Central Trade Unions are organizing Parliament March on 05.10.2014).

3. It is further decided that NFPE will mobilize 15000 employees and FNPO will mobilize 5000 in the Parliament March.

4. It is decided to invite all Central Trade Union leaders to address the Parliament march on 04.12.2014.

DELHI CHALO
MAKE THE PARLIAMENT MARCH A HISTORIC SUCCESS
START MOBILIZATION NOW ONWARDS

Dear friends and College,

NFPE & FNPO calls upon all Circle/Divisional/Branch Unions to start intensive campaign and mobilization at all levels to make the Parliament March a historic success. Let us prepare for an indefinite strike if Government refuses to settle our legitimate demands.

D. Theagarajan
Secretary General
FNPO

R. N. Parashar
Secretary General
NFPE

Postal JCA (NFPE & FNPO)
आंदोलन के मांगपत्र

1. ग्रामीण डाक सेवकों को सातवें वेतन आयोग के कार्यबिंदुओं (टर्म्स ऑफ रैफरैंस) में शामिल किया जाये। जी.डी.एस. को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाये तथा बिना किसी भेदभाव के विभागीय कर्मचारियों के समानुपातिक सभी लाभ दिये जायें।
2. कैजुअल पार्टटाइम तथा कटिंजैंट कर्मचारियों के वेतन भत्तों का दिनांक 1-1-2006 से जब से छठे वेतन आयोग के बाद विभागीय कर्मचारियों का वेतन संशोधित किया है तब से पुनर्निर्धारण किया जाये।
3. दिनांक 1-1-2014 से सभी उद्देश्यों के लिए तथा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी 100 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय किया जाये।
4. सभी कर्मचारियों को जी.डी.एस. सहित 1-1-2014 से 25 प्रतिशत वेतन अंतरिमराहत के रूप में प्रदान किया जाये।
5. नयी पेंशन स्कीम को समाप्त किया जाये तथा 1-1-2014 से पहले व बाद के सभी कर्मचारियों को पुरानी वैधानिक पेंशन स्कीम में रखा जाये।
6. अनुकंपा आधारित नियुक्तियों के लिए 5 प्रतिशत की सीमा समाप्त की जाये तथा रेलवे की तरह सभी पात्रों को नियुक्ति दी जाये। जी.डी.एस. के लिए न्यूनतम 50 पॉइंट की शर्त को समाप्त किया जाये।
7. सभी कैडर के सभी खाली पदों मेलमोटर सर्विस तथा जी.डी.एस. सहित को भरा जाये।
   (क) सीधी भर्त्ती द्वारा
   (ख) डी.पी.सी. आयोजित कर प्रोन्नति देकर
   (ग) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर
8. जे.सी.ए. (डिपार्टमेंटल काउंसिल) स्टाफ साइड द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आधार पर डाक विभाग आर.एम.एस., एम.एम.एस. तथा पोस्टल एकाउंटस में कैडर रीस्ट्रक्चरिंग को लागू किया जाये।
9. एम.ए.सी.पी. संबंधित मु-ों का समाधान किया जाये।
   (अ) विभागीय परीक्षा पास कर जो प्रोन्नति प्राप्त की गयी है उसे एम.ए.सी.पी. के लिए नहीं गिना जाये तथा जोधपुर कैट निर्णय को लागू किया जाये।
   (व) गैर राजपत्रित पदों के लिए वैच मार्क लागू नहीं किया जाये।
   (स) एम.ए.सी.पी. में भी जूनियर के साथ वेतन की स्टैपिंग की जाये।
   (द) प्रोन्नति के क्रम में वेतन निर्धारण किया जाये न कि ग्रेड पे के क्रम में।

10 पोस्टमास्टर कैडर के मु-ों का समाधान किया जाये।
   (क) निरीक्षक डाकघर परीक्षा के लिए अनुमति दी जाये।
   (ख) समान पदों पर सामान्य की तरह एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति में सेवा शर्तों में रियायत दी जाये।
   (ग) सभी पी.एस. ग्रुप 'वी', पी.एम. ग्रेड-3 तथा ग्रेड-2 पदों को पात्र कर्मचारियों द्वारा भरा जाये तथा तब तक हेडहॉक प्रमोशन दिये जाये।
   (घ) सीनियर पोस्टमास्टर तथा चीफ पोस्टमास्टर के 100 प्रतिशत पदों को पोस्टमास्टर कैडर के लिए नियमित किया जाये तथा पी.एम. कैडर कर्मचारियों के लिए अलग से सर्किल ग्रेडेशन लिस्ट बनायी जाये।

11. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए पूर्ण माइलेज एलाउंस दिया जाये तथा कार्य के घंटे तय किये जाये तथा जिम्मेदारी भी तय की जाये तथा अलग कैडर बनाया जाये।
12. आर.एम.एस. तथा प्रशासनिक कार्यालयों के कैशियरों की तरह डाकघरों के ट्रैजरर को कैश हैंडलिंग एलाउंस दिया जाये।
13. पोस्टओफिस तथा आर.एम.एस. एकाउंटेंट को दिये जाने वाले विशेष भत्ते को प्रमोशन की स्थिति में वेतन निर्धारण में शामिल किया जाये। क्योंकि प्रमोशन वाले पद पर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं।

14. आई.टी. मॉडर्नाइजेशन प्रोजैक्ट से संबंधित सभी मुद्दों जैसे कि कंप्यूटरीकरण, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तथा कोरइश्योरेंस सॉल्यूशन आदि का समाधान किया जाये।
    (क) आउटडेटेड कंप्यूटर तथा संबंधित सामान को नये से बदला जाये।
    (ख) बैंडविथ तथा नैटवर्क की क्षमता बढ़ायी जाये।
    (ग) छुट्टी की अवधि के दौरान प्रयोग करने वाले की समस्याओं का समाधान किया जाये।
    (घ) सी.वी.एस., सी.आई.एस. के डाटा पूरी तरह साफ होने तक 'गोलाइब' की जल्दबाजी बंद की जाये।
    (ड़) सी.वी.एस. तथा सी.आई.एस. के क्रियान्वयन में सभी मदद दी जाये तथा उत्पीड़न बंद किया जाये।
    (च) हैड पोस्टमास्टरों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की जाये।
15. सचिव डाक विभाग के साथ जे.सी.एम. (डिपार्टमेंटल काउंसिल) मीटिंग, पीरियोडिकल मीटिंग, स्पोर्टसबोर्ड, तथा वैलफेयरबोर्ड की मीटिंग शीघ्र आयोजित की जाये। स्पोर्टसबोर्ड तथा वैलफेयरबोर्ड में नौमीनेशन मांग कर स्टाफ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।
16. चीफ.पी.एम.जी. के साथ रीजनल जे.सी.एम. तथा चतुर्थमासिक मीटिंगें, रीजनल रीजनल पी.एम.जी. के साथ द्विमासिक मीटिंगें तथा मंडलीय स्तर पर मासिक मीटिंगें आयोजित की जाये। निदेशालय स्तर पर डिवीजनल तथा सर्किल मीटिंगों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनायी जाये।
17. सभी स्तरों पर डी.पी.सी. आयोजित करने में अत्यधिक देरी न की जाये तथा सभी पात्र कर्मचारियों को प्रोन्नति प्रदान की जाये।
18. चीफ.पी.एम.जी., पी.एम.जी. तथा डी.पी.एस. के सभी खाली पदों पर नियुक्ति की जाये। इस समय तमाम पद खाली पड़े हैं तथा अतिरिक्त प्रभार व संयुक्त ड्यूटी के आदेश किये जा रहे हैं जो कि सेवाओं को प्रतिगामी रूप से प्रभावित कर रहे हैं तथा स्टाफ संबंधित मामलों के निस्तारण में देरी हो रही है।
19. कैंटीन कर्मचारियों के लिए नये भर्त्ती नियम अधिसूचित कर सभी विभागीय कैंटीन तथा टिफिन रूमों में खाली प़डे पदों पर भर्त्ती की जाये तथा डाउनसाइजिंग की परिधि में खाली तथा समाप्त पदों को पुनर्जीवित किया जाये।
20. जी.डी.एस. के टी.आर.सी.ए. को पूर्णसंरक्षित किया जाये तथा जी.डी.एस. के लिए मैडिकल बिल के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाये। किसी भी परिस्थिति में टी.आर.सी.ए. को कम नहीं किया जाये। कैशहैंडलिंग नौर्म्स को संशोधित किया जाये।
21. रूल 9 केसों का समयवद्ध तथा त्वरित गति से निपटान किया जाये तथा निदेशालय स्तर पर लंबित रिव्यू तथा रिवीजन पिटीशनों का भी निस्तारण शीघ्र किया जाये।
22. सभी लंबित बिलों की स्वीकृति तथा पर्याप्त फंड का आवंटन
    (क) पी.एल.आई.। आर.पी.एल.आई. इंसेंटिव
    (ख) मेडिकल बिलों का भुगतान।
    (ग) टूर टी.ए. बिल
    (घ) ओ.टी.ए. बिल
23. रेलवे के समकक्ष ओ.टी.ए. की दरें बढ़ाई जायें।
23. (क) सभी सर्किल / रीजनल ऑफीस / डी.पी.एल.आई. ऑफिस कोलकाता को सर्किल प्रोसेसिंग के रूप में कार्य करने दिया जाये जबकि मेककैमिस द्वारा निपत बढ़ोतरी की दिशा में कोर इंशोरेंस सौल्यूशन लागू किया जा रहा है।
    (ख) डाक विभाग स्थापना अनुभाग सं. 43-47/2013-पीई-2 दिनांक 9 जून 2014 द्वारा आदेश 615 पदों का डायवर्जन रोका जाये (सर्किल ऑफिस से 576 पद तथा ए.पी.एस. पी.एल.आइ. सैल से 39 पद)
    (ग) पी.एल.आई./आर.पी.एल.आई. के विकेंद्रिकरण के नाम पर सर्किल कार्यालयों के स्टाफ का उत्पीड़न बंद किया जाये।

25. रविवार तथा छुट्टी के दिन कुछ सर्किलों में जारी उत्पीड़न बंद किया जाये तथा सर्किल / रिजनल तथा डिवीजनल अधिकारियों द्वारा स्टाफ का उत्पीड़न बंद किया जाये। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक तथा दिल्ली सर्किल।
26. सभी सर्किलों को विभागीय इमारतों, स्टाफ क्वाटरों तथा आर.एम.एस. रेस्टहाउसों में निर्माण कार्य, मरम्मत रखरखाव के लिए पर्याप्त फंड आबंटित किया जाये।
27. डाक विभाग में भ्रष्टाचार निवारण के लिए कठोर कदम उठायें जायें तथा जो भ्रष्टाचार व फ्रॉड में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये मुख्य अभियुक्त को सजा देने के बजाय कंट्रीब्यूटरी नैग्लीजेंस के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित न किया जाये।
28. मेलमोटर सर्विस में असि. मैनेजर / मैनेजर तथा सीनियर मैनेजर के सभी खाली पदों पर भर्त्ती की जाये।
29. सभी खाली पोस्टमैन तथा एम.टी.एस. पदों पर स्थनापन्न व्यवस्था की जाये जहां जी.डी.एस. उपलब्ध नहीं है। वहां आउटसाइडर को लगाया जाये।
30. डोर टू डोर डिलीवरी के लिए वर्तमान टाइम फैक्टर को लेकर दिनांक 25/5/1979 के आदेश को संशोधित किया जाये।
31. एल.डी.सी. में जनरल लाइन के लिए पी.एस. ग्रुप 'बी' पदों का प्रतिशत बढ़ाया जाये तथा पी.ए.सी.ओ./पी.ए.एस.वी. सी.ओ. तथा सॉर्टिंग असि. को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाये।
32. चीफ.पी.एम.जी. के द्वारा संस्तुति के आधार पर और एल-1 ऑफिस खोले जायें जैसा कि आंध्र प्रदेश में गुंटकल आर.एम.एस.।
33. एस.वी.सी.ओ. स्टाफ की ए.पी.ए.आर. (सी.आर.) लिखने के लिए डिवीजनल हैड के स्थान पर ए.ओ. (एस.वी.सी.ओ.) को अधिकृत किया जाये तथा सेविंग बैंक संबंधी काम एस.वी.सी.ओ. को नहीं दिया जाये।
34. अच्छी क्वालिटी की वर्दी तथा किट आइटम की शीघ्र आपूर्ति की जाये तथा पुराने स्पैसीफिकेशन को बदला जाये।
35. जी.एम. (वित्त) पोस्टल एकाउंट्स चैन्नई द्वारा की जा रही उत्पीड़न कार्यवाहियों पर रोक लगायी जाये। सैकड़ों कर्मचारियों को चार्जशीटें दी गयी है। जी.एम. ने डी.डी.जी. (पी.ए.एफ.) के निर्देशों को भी अनसुना कर दिया है।
36. एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों के दिसंबर 2012 की जे.ए.ओ. पार्ट-2 परीक्षा के अंकों की पुन: समीक्षा की जाये क्योंकि यह परीक्षा पुराने भर्त्ती नियमों के आधार पर आयोजित की गयी थी। उक्त पद आज पत्रित ग्रुप डी की श्रेणी में आते हैं अत: समीक्षा आवश्यक है।
37. खाली पड़े जी.डी.एस. मेल मैन के कुल कार्य के घंटों के आधार पर एम.टी.एस. के उचित पद सृजित किये जाये जिससे समस्या का समाधान हो सके।
38. एच.एस.जी-1 के भर्त्ती नियम शीघ्र जारी किये जायें तथा सभी डाकघर निरीक्षक के लिए मार्क एच.एस.जी.-1 पदों को जनरल लाइन को दिया जाये जैसा कि जे.सी.एम. डिपार्टमेंटल काउंसिल मीटिंग में तय हुआ था।
39. पोस्टमैन/मेलगार्ड तथा एम.टी.एस. के भर्ती नियमों में संशोधन करो तथा खुले बाजार से भर्ती बंद करो। (सीनियोर्टी) वरीयता के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करो।

March to Parliament On 4th December 2014

Dear Colleagues,

This is to inform you that, for 'March to Parliament' on dt. 4-12-2014 you can book your tickets in advance. No TA or DA will be paid from CHQ. **- T.N. Rahate, General Secretary**

प्रिय साथियों,

आपको सूचित किया जाता है दिनांक 4-12-2014 'मार्च टू पार्लियामेंट' के लिए आप टिकट एंडवांस में बुक कर सकते हैं किंतु सी.एच.क्यू की ओर से कोई TA या DA नहीं दिया जायेगा। **- टी.एन. रहाटे, जनरल सेक्रेटरी**

U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C

National Union of Postal Employees Postmen & Group-D/MTS

(Recognised by Government of India)

Central Head Quarters, Delhi-110 054

C.H.Q. : Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, Delhi - 110 054 • Tel.: 011-23818330 • Fax 011-23321378

Ref. No.: FNPO/MACP/2013 **Date :** 26-01-2013

To,

The Secretary (P), Department of Posts,
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001

Subject : Request for grant of MACP by ignoring TBOP/BCR as per ACP formula

Respected Madam,

It is noticed with great concern that while granting MACP to Central Government Employees as per Annexure I point 5, the ACP promotion are not taken into account.

In our Postal Department the SBCO and some other Staff covered with ACP is getting the MACP as per above Annexure I point 5.

But Post Office Staff having TBOP/BCR is deprived with this exemption i.e. ACP formula. Union therefore request that Postal Staff should be granted MACP by ignoring TBOP/BCR and TBOP/BCR may be treated as ACP.

Kindly issue the clarifactory Orders on the issue and if any Orders are already issued please arrange to supply a copy of that Order.

We felt sorry for late submission of this issue, as it brought to our notice from staff concerned please.

Thanking you,

Yours Sincerely

(T.N. RAHATE)
General Secretary and
President FNPO

हमारी मांग डिपार्टमेंट ने मान ली है। इसलिए डिपार्टमेंट ने आदेश क्रं. 1-20/2008-PCC dated 04-11-2013 जारी किये हैं।

The Department has considered our demands and has issued Order No. 1-20/2008-PCC dated 04-11-2013

Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988

No. 31011/3/2014-Estt. (A-IV)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training
****

North Block, New Delhi-110 001
Dated : 26th September, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 - Relaxation to travel by Air to visit NER and A&N.

The undersigned is directed to say that in relaxation to CCS (LTC) Rules, 1988, it has been decided by the Government to permit Government servants to travel by air to North East Region (NER), Jammu and Kashmir and Andaman & Nicobar Islands (A&N) as per the following scheme -

(i) All eligible Government servants may avail LTC to visit any place in NER/A&N against the conversion of one block of their Home Town LTC. Fresh recruits are also eligible for this benefit against conversion of one of the three Home Towns in a block of four years applicable to them.

(ii) Government servants entitled to travel by air can avail this LTC from their Headquarters in Economy class.

(iii) Government servants not entitled to travel by air may be permitted to travel by air in Economy class in the following sectors:

a. Between Kolkata/Guwahati and any place in NER.

b. Between Kolkata/Chennai/Bhubaneswar and Port Blair.

c. Between Delhi/Amritsar and any place in J&K.

Journey for these non-entitled employees from their Headquarters up to Kolkata/ Guwahati/Chennai/Bhubaneswar/Delhi/Amritsar will have to be undertaken as per their entitlement.

(iv) Air travel is to be performed by Air India in Economy Class only and at LTC-80 fare or less.

(v) Air travel by non-entitled officers on the sectors mentioned in item (iii) above may be permitted while availing LTC to any place in India (4 year Block) also.

(vi) Air Tickets to be purchased directly from the airlines (Booking counters, website of airlines) or by utilizing the service of Authorised Travel Agents viz. 'M/s Balmer Lawrie & Company', 'M/s Ashok Travels & Tours' and 'IRCTC' (to the extent

IRCTC is authorized as per DoPT's O.M. No. 31011/6/2002-Estt. (A) dated 02-12-2009) while undertaking LTC journey. Booking of tickets through other agencies is not permitted.

2. These orders shall be in operation for a period of two years from the date of issue of this O.M.

3. All the Ministries/Departments are advised to bring it to the notice of all their employees that any misuse of LTC will be viewed seriously and the employees will be liable for appropriate action under the Rules. In order to keep a check on any kind of misuse of LTC, Ministries/Departments are advised to randomly get some of the air tickets submitted by the officials verified from the Airlines concerned with regard to the actual cost of air travel vis-a-vis the cost indicated on the air tickets submitted by the officials.

4. In their application to the staff serving in the Indian Audit and Accounts Department, these Orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

Sd/-
(B. Bandyopadhyay)
Under Secretary to the Govt. of India
Ph. (011) 23040341

To
All Ministries/Departments of the Government of India.

We are happy to inform all the members of NUPE P-IV that the Memorandum on Sectional Issues Relating to Postman, MTS & Allied Cadres submitted by our Union to 7th CPC has been acknowledged by the Commission

7th Central Pay Commission
Acknowledgement Slip

The receipt of your letter number **Nil dated 2014-07-22** with inputs on the Subject **Memorandum on Sectional Issues Relating to Postman, MTS & Allied Cadres** sent in response with reference to the Commission's letter / notice number is hereby acknowledged. This is a computer generated acknowledgement and your acknowledgement ID is **CPCL001219.**

Dated 02-09-2014

To,
Shri T.N. Rahate
General Secretary
National Union of Postal Employees Postmen,
Tank Road Post Office, Mumbai-400033

U.N.I. F.N.P.O. I.N.T.U.C

National Union of Postal Employees Postmen & Group-D/MTS

(Recognised by Government of India)

Central Head Quarters, Delhi-110 054

C.H.Q. : Dalvi Sadan, Khurshid Square, Civil Lines, Delhi - 110 054 • Tel.: 011-23818330 • Fax 011-23321378

Ref. No.: NU/P-IV/Agenda/Periodical Meeting/1/2014 **Date :** 01-10-2014

To,

The Secretary (P), Department of Posts,
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001

Kind Attention : Shri Arun Malik, Director (SR & Legal), Dak Bhawan

Subject : Agenda for **ensuing Periodical Meeting** with representatives of FNPO/National Union of Postmen Group 'D' MTS, CHQ, Delhi-110054

Respected Madam/Sir,

The Agenda for ensuing Periodical meeting with NU P-IV Circle representative is furnished below.

Shri K.V. Kurudigi, AGS, NUPE P-IV, Camp at - Bangalore GPO-560001 in Karnataka Circle will attend the periodical meeting alongwith the **undersigned.**

It is therefore requested for cause issue instructions to **Karnataka Circle, Bangalore GPO-1 and Maharashtra, RO (MR) Mumbai East Division** to relieve both of us **well in time to attend the meeting.**

Thanking you,

Yours Sincerely

(T.N. RAHATE)
General Secretary and
President FNPO

CC for information and necessary action

1. Shri D. Theagarajan,
   Secretary General, FNPO,
   T-24, Atul Grove Road,
   New Delhi-110001

Ensuing Periodical Meeting Agenda

Item No. NU/P-IV/1/2014 : A) Non-Recruitment of 100% on vacant post of Postman Group D MTS from GDS/Casual Labor Staff for the year 2009 to 2012 from neighboring Division (Case of all metro cities and all Circles in other cities).

I would like to bring it to your kind notice the Directorate Order of filling of 100% vacant post of Postman Group D MTS for the **year 2009 to 2012** from GDS/Casual Labor Staff (within Division and neighboring Division). (For example, Mumbai GPO and Mumbai Region in other Divisions).

But many vacant post are **not filled in all metro cities and all Circles in other cities** for the **year 2009 to 2012** those which are vacant due to Retirement, Promotion, Voluntary Retirement, Death and Dismissal etc.

In fact, **all metro cities and all Circles in other cities** are having vast area and in almost all **cities** expansions in multi-storied buildings, malls, and business centre is increasing, therefore delivery work is also increasing and present staff strength of Postman Group D MTS is not sufficient. The Circle/Regional/Divisional Office has not taken action to fill up the 100% vacant post of **Postman Group D MTS for the year 2009 to 2012.**

Union demand -

1. For the year 2009 to 2012 all vacant post of Postman Group D MTS 100% should be filled in from GDS/Casual Labor Staff, if those are not available in parent Division, **neighboring Division** GDS/Casual Labor may be recruited.
2. As per Department Rule one L/R should be created / provided for **each 10 official staff of each cadre,** Union demand for creating **L/R post for Postman Group D MTS** staff.
3. If GDS/Casual Labor are not available for recruitment on vacant post of Postman Group D MTS at **all metro cities and all Circles in other cities,** Orders may be issued to fill up these post from **neighboring** Division from GDS/Casual Labor Staff.
4. Please arrange to call for report from **all the Circles** regarding position of non-filling of 100% vacant post of Postman Group D MTS for the year 2009 to 2012 from **within Division or neighboring Division** from GDS/Casual Labor Staff.
5. **It is also requested to send clarification from your Office to all the Circle Head that neighboring Division means other Divisions within Regions, because IPS/DPS cadre assumed that neighboring Division means RMS and so 100% recruitment was not done.**

B:- Notification for Direct Recruitment of Postmen/MTS and fill up the posts 100% vacant post from 2012 to2013 and 2014

1. Notification for Direct Recruitment of Postmen/MTS for last three years is not yet published. This is necessary to give notification for direct recruitment of Postmen/MTS at the earliest and fill up the posts remaining all vacant post from 2012 to 2013 and 2014
2. Filling up the posts of MTS at Administrative Offices.
3. The posts of MTS at various administrative offices like RO/CO/DO/PSD etc are vacant over a number of years. Necessary action is required for immediate filling of these posts.

Item No. NU/P-IV/2/2014 : DG Order No. 1-20/2008-PCC dated 4-11-2013 Para 5 to ignore TBOP/BCR and Pay Re-fixation should be made w.e.f. 1-9-2008 by 3% increment and next GP 1900, 2000 and 2400, 2800, Case of MTS, Postman, Mailguard in all Circles in DDOs.

A)- According to **original Orders of MACP Para 5** those who got ACP I & II, the fixation of their pay w.e.f. 1-9-2008 by 3% increment + next Grade Pay 1900, 2000 and 2400, 2800 only for those staff who got 5th CPC pay upgraded in 6th CPC.

Group D 5th CPC Scale 2550-55-2660-60-3200 upgraded to 2750-70-3800-75-4400; likewise Postman and Mailguard upgraded 3050-70-3750-80-4590 to 3200-75-4900 in 6th CPC. Those who got TBOP/BCR before 1-1-2006 were fixed with one and the same grade **MTS Grade Pay 1900 and 2000 and Postman GP 2400 and 2800.** Therefore, they are denied the benefit as their TBOP/BCR are **not ignored** as per with other Central Government Department.

This fact was noticed by Service Union with the Department and it so requested to issue Orders **to ignore the TBOP/BCR** while fixation of MACP. Accordingly Order No. 1-20/2008-PCC dated 4-11-13 were issued.

But, I am very sorry to point out that the DDOs and even RO, CO, Accounts Officer and DAPs not followed the Orders and were asking for **clarifications to DAP and Directorate.** And so the MTS Postman still did not get pay refixation, inspite of Orders being issued **11 months back.** Instead, recovery (in lakhs of rupees) is being made from the retiring Postman and MTS staff. For example in Mathura HO and in Mumbai GPO.

It is therefore requested for cause issue instructions to all the DDOs in all Circles to draw and disburse the pay re-fixation as per Directorate Orders No. 1-20/2008-PCC of dated 4-11-2013. TBOP-BCR should be ignored as per this Order and help to remove the unrest amongst the staff for delay in pay re-fixation of MACP.

B)- Grant of IInd and IIIrd MACP under MACP Scheme:- As per original Orders of MACP Para 5 all Central Government Employees whose pay as per 5th CPC is upgraded (Postman and MTS Cadre) by 6th CPC, their TBOP and BCR before 1-1-2006 are to be ignored and they should be granted IInd and IIIrd MACP after completion of 20 and 30 years service respectively.

As per original Orders of MACP Para 5 all Central Government Employees whose pay as **per 5th CPC is upgraded** (Postman and MTS Cadre) by 6th CPC, their TBOP and BCR before 1-1-2006 are to be ignored and they should be **granted IInd and IIIrd MACP after completion of 20 and 30 years service respectively.**

In our Postal Department having TBOP BCR the Orders to **ignore** were not in existence.

But the Service Union brought to the notice of Department this fact of anomaly compared to other Central Government Department.

The Department therefore issued **Orders No. 1-20/2008-PCC dt. 4-11-2013** through which it is clear that as per original Order of MACP Para 5, as per ACP, the Postal Department TBOP/BCR should be **ignored** while giving MACP IInd and IIIrd (for example:- copy of Order enclosed). For example, Maharashtra Circle in Mumbai Region in Mumbai City East Division (below).

Sr. No.	Name of the Postman and MTS Official	Date of entry in Group 'D'/ MTS Cadre	Date of entry in Postman Cadre	Grant of TBOP Promotion	After ignoring TBOP and completion of 20 years of service He is eligible for II MACP - (TBOP Employees Same date double fixation) i) 3% Increment and next GP and ii) 20 years of service for II MACP. 3% Increment and next GP	After Ignoring BCR and completion of 30 years of service - He is eligible for IIIrd MACP (As per qualifying service)
1.	Shri N.G. Masurkar	23-10-1978	01-09-1987	14-10-2003	01-09-2008	23-10-2008
2.	Shri P.N. Sawant	10-02-1981	08-12-1987	29-12-2003	01-09-2008	10-02-2011
3.	Shri V.S. Chowdhari	20-03-1979	27-04-1985	2001	01-09-2008	20-03-2009
4.	Shri N.T. Kengar	16-09-1980	16-09-1987	12-10-2003	01-09-2008	16-09-2010
5.	Shri P.S. More	23-10-1978	16-06-1983	23-06-1999	01-09-2008	23-10-2008
6.	Shri N.M. Kedare	06-02-1981	27-04-1985	26-05-2001	01-09-2008	06-02-2011
7.	Shri M.B. Hajare	01-03-1983	1987	2003	01-09-2008	01-03-2013
8.	Shri. B.M. Shetye	29-01-1979	1983	1999	01-09-2008	29-01-2009

The MACP should be given as per the table given above, but it is not given as per the above table. So the MACP should be given as per the **Orders No. 1-20/2008-PCC dt. 4-11-2013** issued by the Department.

But since 11 months period is lapsed but no any action is taken by the concerned Authorities.

Union therefore demands - As per **Orders No. 1-20/2008-PCC dt. 4-11-2013** those staff who got TBOP or BCR before 1-1-2006 may be granted **MACP IInd and IIIrd** after completing **20 and 30 years** of service by **ignoring TBOP/BCR.**

Item NU/P-IV/3/2014 - Combined working of Mumbai Region and Chief PMG Office work by Chief PMG, Maharashtra Circle Office Staff and Officer (as previously was in practice)

This case of combination of work of Mumbai Region into office of the CPMG, Maharashtra has been already taken with the CPMG, Maharashtra as it was in past in existence. Since last so many years or we may say that since opening of separate Mumbai Region only PMG and DPS two posts were there and rest all other staff of CPMG office was dealing the work of Mumbai Region. **The copies of letters addressed in details are enclosed herewith for ready reference.** The clerical and other posts of Mumbai Region may be redeployed to proposed **Telangana Circle.** And working staff & officers posted in Mumbai Regional Office should be transferred to Circle Office vacant posts and may be utilized for Business Development and PLI Works. (Now, the employees of CO Maharashtra are suffering from shortage of staff and officers, for example, PA MTS alongwith IP-SDI, ASP, Group B and A officers.

The work of Mumbai Region staff and officers should be given to (CO) CPMG Office staff and officers. So they can handle the work of CPMG office in Mumbai Region and the total staff strength of 77 may be redeployed to newly proposed Telangana Circle.

Sanctioned Strength of Mumbai Region

SL. No.	Category of Post	Sanctioned Strength
1.	Group A (JTS/STS)	1
2.	Group A (PSS)	4
3.	Group A (GCS)	1
4.	Steno (Grade I)	1
5.	ASPO	5
6.	IPO	2
7.	AO/AAO	4
8.	Supervisors	5
9.	PA	38
10.	Steno	3
11.	Group D (TC/NTC)	13
	Total	**77**

Thanking you,

Yours Sincerely

(T N RAHATE)
General Secretary & President FNPO

जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट

पृष्ठ 1 का शेष.....

24-9-14 को जयपुर गया। जयपुर में CPMG से मिलकर राजस्थान की समस्या खासतौर पर बिकानेर भरतपुर भीलवाड़ा और जयपुर की समस्याओं के बारे में चर्चा की। P-III सर्कल सचिव का निलंबन त्वरीत र- करने की मांग की। तुरंत फोन से DPS अजमेर के साथ बातचीत करके डिटेल लिखित रिपोर्ट मांगी और उसके बाद CPMG सही निर्णय देकर निलंबन को जल्द से जल्द र- करेंगे। बिकानेर के SSPOs को तुरंत सूचना देकर 160 सभासद के अथोराइजेशन फार्म लेकर जुलाई से चंदा पे से रिकवर करने के आदेश दिये। बिकानेर में छोटी-छोटी बातों पर सस्पेंड किये गये दो PA का तुरंत मिले निलंबन र- करेंगे। और SSPO, SPOs और DPs लेवल के अधिकारी सिस्टर यूनियन को फेवर करके हमारे संगठन के सभासद कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं। इस बारे में उदाहरण CPMG को दिया। सभी डिवीजन के **अधिकारियों को मीटिंग लेकर समझाया जाये** कि किसी भी यूनियन को जानबूझकर और दूसरे यूनियन की बात पर परेशान नहीं करना है। यह सूचना दिया जाये। हमारे साथ P-IV और P-IV सर्कल सचिव साथ में थे।

DPS (HQ) के साथ बातचीत हुई। उनको भी किसी गैर समझ से भड़काया गया है। उनको समझाने की कोशिश की दुबारा सर्कल सचिव के साथ जाकर सच्चाई सामने रखकर उनकी नाराजगी खत्म करेंगे।

25-9-2014 को भोपाल (MP) सर्कल में रहा। होशंगाबाद डिवीजन में नये IPS ने SSPOs जाईंट किया है। उनको ASPS ने हमारे सर्कल सचिव और यूनियन के बारे में मिसगाईड किया इसलिए अपना अधिकार दिखाने के लिए और संगठन को दबाने के लिए उनको गलत **निलंबित** किया। उस बारे में DPS (HQ) से सच्चाई सामने रखने के बाद तुरंत निलंबन र- करने के आदेश दिये और उनका निलंबन 1-10-2014 से निलंबन र- करके ड्यूटी जाईंट की, और भी पोस्टमैन MTS की भर्ती, अधिकारों की दबाब के बारे में चर्चा की। अधिकारियों का दबाब न करने की सूचना दी जायेगी।

30-9-2014 मुंबई (महाराष्ट्र) में रहा। मुंबई महाराष्ट्र में रहकर हमें महाराष्ट्र समस्या के बारे में PMGs, DPS, CPMG से मिलकर हल करने की कोशिश करते रहे। GDS और कैज्युअल लेबर को MTS बनाने के लिए कामयाब हुए। और मुंबई CHQ ऑफिस में रोज बैठकर सारे सर्कल की समस्या फोन द्वारा या पत्र द्वारा CPMG, Secretary (P), Members (PSB) और संबंधित अधिकारियों को समस्या के बारे में व्यवहार करके फोन से बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करते रहा।

सभी को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ।

टी.एन. रहाटे

CHQ Quota

All the Divisional Secretaries / Branch Secretaries are requested to send CHQ Quota of Rs. 9/- (Rs. Nine) each member per month to **Shri Jagdish Sharma, Treasurer (CHQ), Camp : I.P.H.O., New Delhi-110002. M.:** 09911 226062/ 09899 608399 / 08595 045985 as early as possible.

RNI No. 57368/94 **No. DL (N) / 066/ 2012-14**
Date of Publication :- 24 of every month **OCTOBER, 2014**

No Trade Union Facilities Given to Bharatiya Postal Employees Federation and its affiliated Unions.

No Trade Union faciliites are given to Bharatiya Postal Employees Federation and its affiliated Unions as per recognised FNPO and NFPE Federation. Only Informal meetings with Senior Officers can be conducted. No Minutes will be provided after the meeting.No Special Leave will be granted for CWC meeting or Divisional/ Circle/All India Conference. So the Department has issued corrigendum. This is being published for your information.

भारतीय पोस्टल एम्पॉलाईज फेडरेशन और इससे संलग्न यूनियनों को कोई ट्रेड यूनियन सुविधाएं नहीं दी जाएंगी

भारतीय पोस्टल एम्पॉलाईज फेडरेशन और इससे संलग्न यूनियनों को कोई ट्रेड यूनियन सुविधाएं (facilities) नहीं दी गई है जैसी मान्यता प्राप्त फेडरेशन FNPO और NFPE को दी गई है। केवल वे डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरों के साथ इनफार्मल (मौखिक) सभा ले सकते है। इसमें उनको कोई लिखित मिनीट (जवाब) नहीं दिया जाएगा। उनको CWC मीटिंग तथा डिवीजन/सर्कल/अखिल भारतीय अधिवेशन के लिए भी कोई भी खास (स्पेशल) छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका डिपार्टमेंट की ओर से कोरीजंडम निकला है, उसे नीचे आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं।

No. 8 / 20 / 2013-SR
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts

Dak Bhawan, New Delhi.
Dated the 25th July, 2014

CORRIGENDUM

Subject : Trade Union Facilities to Bharatiya Postal Employees Federation and its affiliated unions.

This has reference to this Department's communication of even number dated 24th June, 2014 on the subject mentioned above. Sl. No. (2) of the said communication i.e. "Meetings with Senior Officers" may be read as :

"Informal meetings with Senior Officers".

This issues with the approval of competent authority.

V. Ramaswamy 25/07/2014
(V. Ramaswamy)

Assistant Director General (SR & Legal)

1. All Heads of Circles.
2. All Postmasters General
3. PPS to Secretary (Posts)
4. All Members/JS &FA / DDGs / Secretary (PSB) / Directors / ADGs of Postal Directorate
5. Secretary General, Bharatiya Postal Employees Federation.
6. All General Secretaries of affiliated Unions of BPEF
7. All Sections of Postal Directorate.

Owner, Publisher, Printer and Editor T.N. Rahate, P&T Colony, Civil Lines, New Delhi-110054
Printed at Vandana Print & Co. 633/634, Daryaganj, Ganj Mirkhan, Delhi-110002